जुलाई, 2026 , वर्ष : 47 अंक : 7

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

तिब्बती एक्टिविस्ट लोबगा रंगज़ेन के लिए एक अस्थायी स्मारक, जिन्होंने 2 जुलाई को न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बत पर चीन के कब्जे का विरोध करने के लिए आत्मदाह कर लिया था।

जुलाई, 2026 , वर्ष : 47 अंक : 5

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

प्रधान संपादक
ताशी देकि

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
मिग्मार छमचो

वितरण प्रबंधक

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर के बाहर लोबगा रांगज़ेन के आत्मदाह पर सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग का ऑफिशियल बयान

समाचार -

समाचार -

Contents

०१. परम पावन १४वें दलाई लामा ने शेवत्सल फोड्रंग ग्राउंड में अपने ९१वें जन्मदिन के जश्न में हिस्सा लिया 2
०२. सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' को लेकर दुनिया भर से तत्काल अपील की 4
०३. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर लोबगा रंगजेन के आत्मदाह पर सिक्योंग पेन्पा शेरिंग का आधिकारिक बयान 6
०४. सीटीए ने आत्मदाह करने वाले तिब्बती लोबसांग पाल्डेन की शहादत के सम्मान में प्रार्थना सभा आयोजित की 6
०५. धर्मशाला में सीटीए और तिब्बतियों ने परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन मनाया 7
०६. आईटीसीओ और हिमालयी परिवार ने नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन मनाया 8
०७. बेल्जियम के विदेश मंत्री ने कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकार पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध समुदाय का मामला है 10
०८. चीन के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति' कानून को लेकर एस्टोनियाई संसद में तिब्बत समर्थक समूह और रीगिकोगु (एस्टोनियाई संसद) के सदस्यों का वक्तव्य 11
९. तिब्बती पहचान पर हमला: सालों की दमनकारी निगरानी के बाद चीन ने फिर से लारुंग गार में बेरहम तोड़-फोड़ शुरू की 12
१०. बेल्जियम, नीदरलैंड और स्पेन में सैकड़ों लोगों ने चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को रद्द करने की मांग की 13
११. विरोध की आग: लोबगा रंगजेन की आत्मदाह पर यूरोप में बसे तिब्बती समुदाय ने जेनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय की अगुआई में शोक मनाया। 14
१२. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी का विरल तिब्बत दौरा, चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को लागू करने और जबरन विलीयकरण की नीतियों को और मजबूत करने का संकेत 15
१३. तिब्बती राजनीतिक कैदियों की विवरणिका- सुल्ट्रिम ग्यात्सो 16

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा

नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की [illegible]

coordinator@indiatibet.net

अपनी बात

दलाईलामा के जन्मदिवस पर उनकी चार प्रतिबद्धताओं की चर्चा

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
श्री श्याम मंदिर, खेतड़ी
जिला–झुंझुनूं (राजस्थान)
मो.–9079352370
E-mail:- shyamnathji@gmail.com

गत 06 जुलाई, 2026 को परमपावन 14वें दलाईलामा के 91वें जन्मोत्सव पर संपूर्ण तिब्बती समुदाय एवं तिब्बत समर्थकों ने भारत सहित विष्व के विभिन्न देषों में अनेक प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किये। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें हार्दिक षुभकामनायें दीं तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की मंगल कामना की। नोबल षांति पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय सम्मान, उपाधि एवं अलंकरण प्राप्त कर चुके दलाईलामा लगातार अपनी चार प्रतिबद्धताओं पर जोर देते रहे हैं। उनके इसी रचनात्मक प्रयास ने उन्हें विष्वमानव तथा तिब्बत के प्रष्न को अंतरराष्ट्रीय प्रष्न बना दिया है।

दलाईलामा की पहली प्रतिबद्धता षांति, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम आदि मानवीय मूल्यों के प्रति है। उनके अनुसार ये मूल्य सभी प्राणियों के लिये उपयोगी हैं। मानव के साथ अन्य जीवों के लिये भी। इस संदर्भ में एक उदाहरण 18 मई, 2026 का। हिमाचल प्रदेष के कांगड़ा जिलांतर्गत धर्मषाला से सटे मैक्लूडगंज के मेन चौक (सरदार पटेल की मूर्ति) पर षाम में उत्तर प्रदेष सरकार के लखनऊ स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध षोध संस्थान के षोध अधिकारी वैद्य अरुण कुमार मिश्र के साथ मैं दलाईलामा संबंधी चर्चा कर रहा था। सरदार पटेल चौक के नजदीक ही दलाईलामा का निवास एवं मंदिर है। वहाँ उनके अनुयाइयों की हर समय भारी भीड़ रहती है। चौक पर अचानक एक काला बिच्छू नजर आया। आकार में बड़ा और बहुत जहरीला भी। हम दोनों उसे मारने के लिये कोई पत्थर ढूँढ़ने लगे क्योंकि थोड़ी ही देर में भीड़ में किसी को भी वह डंक मार सकता था। इसी समय भीड़ में से एक युवक सामने आया और सिर्फ कागज की मदद से उस बिच्छू को पकड़कर एक नाले में डालने लगा। बार–बार बिच्छू बाहर आ जाये लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वह युवक सफल हो गया।

अगले दिन बिच्छू वाली घटना मैंने और अरुणेष मिश्र ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध षोध संस्थान के निदेषक डॉ0 राकेष सिंह को बताई। उन्होंने बिच्छू की रक्षा करने वाले युवक के साहस और धैर्य की प्रषंसा करते हुए इसे दलाईलामा की करुणा का प्रभाव एवं प्रमाण बताया। संसार में सभी जीव–जंतु मिलकर एक दूसरे का संरक्षण–संवर्धन करें तभी संसार का अस्तित्व रहेगा। मनुश्य को भगवान् ने चूँकि विवेक दिया है इसलिये उसे चाहिये कि वह मनुश्य के साथ–साथ अन्य समस्त प्राणियों के प्रति भी सभी मानवीय मूल्यों का उपयोग करे। डॉ0 राकेष सिंह ने बताया कि भगवान् बुद्ध का उपदेष यही है जिसके प्रचार–प्रसार में दलाईलामा लगे हैं।

चूँकि दलाईलामा बौद्ध धर्मगुरु हैं इसलिये उनकी दूसरी प्रतिबद्धता विभिन्न रिलिजन (संप्रदाय, पंथ, मजहब, मत, उपासना पद्धति) के बीच सद्भाव के प्रति है। उनके अनुसार प्रत्येक रिलिजन के अनुयाई अपने रिलिजन के नियमों एवं परंपराओं का ईमानदारी से पालन करें। इसके साथ ही वे अन्य रिलिजन के अनुयाइयों तथा उसके नियमों एवं परंपराओं का भी भरपूर सम्मान करें। सभी रिलिजन पूजा या प्रार्थना के नियमों में भिन्नता के कारण एक–दूसरे से भिन्न हैं लेकिन जिस सर्वोच्च षक्ति की वे अपने–अपने ढंग से पूजा या प्रार्थना करते हैं वह तो एक ही है। सभी उसी एकमात्र सर्वोच्च षक्ति की पूजा–प्रार्थना–उपासना करते हैं इसलिये भिन्नताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की समानता के कारण सभी रिलिजन समान हैं। दलाईलामा इसी को वास्तविक पंथनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) का आधार बताते हैं। यही है सर्वपंथ समादर भाव। इसी भाव के कारण भारत में अनेक संप्रदाय सद्भावपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। विष्व के अन्य देषों में भी ऐसा होना जरूरी है। रिलिजन के नाम पर बढ़ते संघर्श से छुटकारा तभी मिलेगा जब आचार–विचार–व्यवहार में प्रत्येक रिलिजन अन्य रिलिजन का भी सम्मान करने लगेगा।

चूँकि दलाईलामा तिब्बती धर्मगुरु हैं इसलिये उनकी तीसरी प्रतिबद्धता तिब्बत से जुड़ी है। साम्राज्यवादी चीन ने 1959 से स्वतंत्र तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कर रखा है। उसने साजिषपूर्ण नीति लागू करके तिब्बती षिक्षा, संस्कृति, इतिहास तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद कर दिया है। जल स्रोतों की अधिकता के कारण तिब्बत को संसार की छत तथा तीसरा ध्रुव कहा जाता था। इससे कई देष समृद्ध थे। चीन ने जल–स्रोतों को भी बर्बाद कर दिया। चीन सरकार शड्यंत्रपूर्वक तिब्बत का चीनीकरण कर रही है। तिब्बती पहचान की सुरक्षा के लिये आवष्यक है कि चीन के संविधान तथा राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अनुरूप चीन सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करे। प्रतिरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध चीन के पास हों तथा कृशि, षिक्षा सहित अन्य विशय तिब्बतियों को सौंपे जायें। तिब्बत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को स्वायत्तता दी जाये। विष्व समुदाय इसके लिये चीन सरकार पर प्रभावी एवं निर्णायक दबाव डाले।

चौथी प्रतिबद्धता प्राचीन नालंदा परंपरा के प्रति है। विदेषी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भीशण आगजनी कर नालंदा विष्वविद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगषालाओं, रसायनों, उपकरणों, षोधग्रंथों, पांडुलिपियों तथा षोधतकनीकों को नश्ट कर दिया था। उसने आचार्यों, षिश्यों एवं अन्य सहयोगियों की निर्मम हत्या कर दी थी। फिर भी कई आचार्य–षिश्य कुछ ग्रंथादि सामग्री बचाने में सफल रहे। दलाईलामा संसार में भ्रमण कर बताते हैं कि भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा में ज्ञान–विज्ञान का विषाल भण्डार है जो संपूर्ण विष्व के लिए उपयोगी है। प्रसन्नता की बात है कि उनकी प्रेरणा–प्रोत्साहन–आषीर्वाद से भारत की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अंतरराश्ट्रीय स्तर के नालंदा विष्वविद्यालय को स्थापित–विकसित किया है। यह प्राचीन नालंदा विष्वविद्यालय के वैभव को पुनर्जीवित एवं पुनर्प्राप्त करने का सफल सराहनीय प्रयास है।

◆ ०१. परम पावन १४वें दलाई लामा ने शेवत्सल फोड्रंग ग्राउंड में अपने ९१वें जन्मदिन के जश्न में हिस्सा लिया

०७ जुलाई, २०२६

शेवत्सल (लेह, लद्दाख)। ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार, बीते कल यानी ०६ जुलाई, २०२६ को परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन था। इस अवसर पर भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह स्थित शेवत्सल टीचिंग ग्राउंड में इसे बहुत खुशी के साथ मनाया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए जब परम पावन मिनी-बस में सवार होकर अपने आवास से टीचिंग प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे, उस समय रास्ते में श्रद्धालुगण हाथों में सफेद रेशमी स्कार्फ लिए कतार में खड़े रहे। वहां से गुजरते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। प्लेटफॉर्म के पास स्नो-लायन, याक और खास वेशभूषा में नृत्यांगनाएं उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थीं। इनके अलावा थिक्से रिनपोछे उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे, जबकि पारंपरिक लद्दाखी ड्रमर स्वागत में ढोल बजा रहे थे।

परम पावन ने मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे से लगभग २५,००० लोगों की भीड़ का अभिवादन किया। इसके बाद, उन्होंने दिन के जश्न की शुभ शुरुआत के लिए बटर लैंप (मक्खन का दीपक) जलाया। लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लकरुक, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के प्रमुख पेन्पा शेरिंग और थिक्से रिनपोछे ने परम पावन को बुद्ध के मन, वचन और कर्म के प्रतीक भेंट किए।

परम पावन को एक पारंपरिक अनुष्ठान वाले केक के आकार का जन्मदिन का केक भेंट किया गया। उन्होंने केक काटने के बजाय उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया।

इसके बाद शेरिंग दोरजे ने उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, जिन्होंने करुणा से प्रेरित होकर हमें सभी गलत विचारों से मुक्ति दिलाने वाली शिक्षाएं दीं। मैं परम पावन- जिनका नाम जेट्सुन जम्पेल न्गावांग लोबसांग येशे तेनजिन ग्यात्सो है, संघ के सदस्यों, सम्मानित अतिथियों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सीटीए की सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर येशी वांग्मो, निर्वासित तिब्बती संसद की स्पीकर डोल्मा शेरिंग और सीटीए प्रमुख पेन्पा शेरिंग का अभिवादन करता हूं।

दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी लोग आज परम पावन का ९१वां जन्मदिन मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर एलबीए और लद्दाख में रहने वाले तिब्बतियों की ओर से मैं परम पावन दलाई लामा का अभिवादन करता हूं और उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच यहां मौजूद हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे लंबी और स्वस्थ आयु पाएं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों।

इसके बाद, तिब्बत संग्रहालय के निदेशक तेनजिन टॉपधेन ने परम पावन के बारे में एनिमेटेड फिल्मों की सीरीज लॉन्च करने के लिए उन्हें एक आईपैड पर टैप करके परम पावन दलाई लामा को आमंत्रित किया। यह सीरीज तिब्बत हाउस, न्यूयॉर्क द्वारा बनाई गई ग्राफिक बायोग्राफी 'मैन ऑफ पीस: द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ हिज होलीनेस द फोरटिन्थ दलाई लामा' से प्रेरित है।

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने कशाग (सीटीए कैबिनेट) की ओर से एक बयान पढ़ा:

'परम पावन १४वें दलाई लामा के ९१वें शुभ जन्मदिन पर, कशाग तिब्बत के अंदर और बाहर रहने वाले सभी तिब्बतियों की ओर से उन्हें सादर नमन करता है। हम इस अवसर पर उन खास मेहमानों, मठवासी समुदाय के सदस्यों और दुनिया भर के उन लोगों का भी स्वागत करते हैं, जो इस महान अवसर को खुशी और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं।

'कशाग ने पिछले साल को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 'करुणा वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह परम पावन की अपार करुणा के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी चार मुख्य प्रतिबद्धताओं के बारे में वैश्विक जागरुकता को बढ़ावा देने का प्रयास था। इनमें पहली प्रतिबद्धता है बुनियादी मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, दूसरी है हमारी धार्मिक परंपराओं के बीच बेहतर सद्भाव को बढ़ावा देना, तीसरी है तिब्बत की अनूठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ 'लैंड ऑफ स्नो (बर्फ की भूमि)' के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में योगदान देना और चौथी है प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में जागरुकता और समझ को फिर से जगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

'ये प्रतिबद्धताएं सभी जीवित प्राणियों और दुनिया के लिए स्थायी शांति, सद्भाव और भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक असाधारण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। सीटीए ने इन प्रतिबद्धताओं के बारे में लोगों को बेहतर ढंग से बताने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही, धार्मिक, मानवीय और सामुदायिक सेवा गतिविधियां भी की गई हैं, जैसे कि प्रार्थना के झंडे लगाना, कत्ल के लिए ले जाए जा रहे जानवरों को बचाना, कंग्युर का पाठ करना और मंत्रों का जाप करना। इसके अलावा, सार्वजनिक सेवा और करुणा के कई कार्य भी किए गए हैं, जैसे कि बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को भोजन, कपड़े और बिस्तर दान करना, आदि।'

'पूरे हिमालयी क्षेत्र में कई समूहों और संगठनों ने करुणा वर्ष कार्यक्रम के तहत पौधरोपण, पर्यावरण की सफाई और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह जानकर भी खुशी होती है कि दुनिया भर के कई शहरों, खासकर अमेरिका के शहरों में, परम पावन के जन्मदिन को आधिकारिक तौर पर 'करुणा दिवस' घोषित किया गया है। यह करुणा, अहिंसा, सर्वधर्म सद्भाव और मानवीय मूल्यों के बारे में परम पावन के संदेश की सार्वभौमिक प्रासंगिकता और स्थायी अपील की एक सशक्त पुष्टि है।'

इसके बाद, एलबीए ने लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश की शिक्षा सचिव सुश्री भानु प्रभा को लद्दाख में स्कूलों को सुधारने के उनके काम के लिए सम्मानित किया। परम पावन ने उन्हें एक फ्रेम किया हुआ प्रमाण-पत्र और बुद्ध की एक मूर्ति भेंट की।

इसके बाद दोरजे स्टाकमो और उनके समूह ने परम पावन और उनके जन्मदिन के सम्मान में कई गीत प्रस्तुत किए। गीतों के बोल में परम पावन का वर्णन इस प्रकार किया गया है, 'हे हस्तकमल देव, आप जो सभी

जीवित प्राणियों को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, हमारे रक्षक पद्मपाणि। आप सूर्य के समान हैं, हमारे लामा, शांति के अग्रदूत, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। आपका ज्ञान और करुणा अंतरिक्ष की तरह विशाल और समुद्र की तरह गहरे हैं।'

इसके बाद परम पावन को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

उन्होंने अपने प्रवचन शुरू करते हुए कहा, 'आज, यहां लद्दाख में लोगों के बीच अटूट विश्वास, भक्ति और मजबूत आध्यात्मिक साहचर्य है। दुनिया भर से भी लोग यहां एकत्र हुए हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दीर्घायु होऊं, और मेरी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि-

जहां कहीं भी बुद्ध की शिक्षाएं नहीं पहुंची हैं,

और जहां कहीं भी वे पहुंची हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो गया है,

वहां मैं, महान करुणा से प्रेरित होकर,

सभी के लिए उत्कृष्ट लाभ और खुशी के इस खजाने की।

स्पष्ट रूप से पहचान करा सकूं।'

परम पावन ने आगे कहा, 'दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी कोई आध्यात्मिक आस्था नहीं है। जब मैं १९५४-५५ में चीन गया था, तो माओत्से तुंग ने मुझसे कहा था कि धर्म अफीम की तरह है। हालांकि, धर्म का पालन करने का मतलब सिर्फ देवी-देवताओं को खुश करना या प्रार्थना करना नहीं है। असल में, यह अपने मन को बदलने और उसे अच्छे कामों की ओर मोड़ने के बारे में है। धर्म के पालन का महत्व मन को शांत रखना और मन को प्रशिक्षित करना है।

'अपनी बात करूं तो, सुबह उठते ही मैं यह प्रार्थना (ऊपर बताई गई) करता हूं, जिसे जे सोंग्खापा ने अपनी किताब 'ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के महान चरण' के आखिर में समर्पण के श्लोकों में लिखा है, 'जहां धर्म नहीं फैला है, या जहां फैला था पर कमजोर पड़ गया है, वहां मैं करुणावश उसे फिर से जीवित करूं और फैलाऊं।'

'हम तिब्बत के तीनों प्रांतों- यू-त्सांग, खाम और अमदो के तिब्बती लोग बौद्ध-धर्म के पक्के अनुयायी हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन गई है, इसलिए हमने अपने मन को अनुशासित करना और मन में शांति बनाए रखना सीखा है।

'अपनी यात्राओं के दौरान मैंने देखा है कि चीनी लोगों पर बौद्ध-धर्म का बहुत प्रभाव है। हम तिब्बती भारत के अलग-अलग हिस्सों में बस्तियों में रहने वाले शरणार्थी बन गए हैं और हमारे भारतीय पड़ोसियों और दूसरी जगहों के लोगों ने तिब्बतियों की सराहना करना शुरू कर दिया है। कृपया मेरे साथ यह प्रार्थना करें, 'करुणा से प्रेरित होकर मैं बुद्ध की शिक्षा को रोशन करूं, उसे वहां फिर से जीवित करूं जहां वह कभी फैली थी पर कमजोर पड़ गई थी, वगैरह।'

'हर कोई दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करता है। मैं भी बोधिचित्त, यानी जागृत मन के अभ्यास के जरिए ऐसा करता हूं। सुबह उठते ही मैं बुद्ध की शिक्षा और सभी प्राणियों के भले के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं हर दिन ऊपर बताई गई प्रार्थना करता हूं और मुझे लगता है कि वह पूरी हो रही है। चीनी लोगों के बीच बौद्ध धर्म फिर से जीवित हो रहा है और तेजी से फैल रहा है और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में लोग प्यार और करुणा की शिक्षा में रुचि ले रहे हैं। दूसरों का भला करने की भावना और दयालुता ऐसी चीजें हैं जिनकी हर जगह लोग तारीफ करते हैं।

'सुबह उठते ही मैं बोधिचित्त, यानी दूसरों का भला चाहने वाले जागृत मन और शून्यता की समझ पर विचार करता हूं।' मैं जहां भी जाता हूं, स्नेहपूर्ण हृदय रखता हूं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं लोगों के बीच स्नेह और सद्भावना फैलाने का प्रयास करता हूं। 'करुणा से प्रेरित होकर, मैं खुशी, कल्याण और भलाई से जुड़े इस खजाने को प्रकाशित करूं।'

'तो, यह मेरा ९१वां जन्मदिन है, मैं ९१ साल का हो गया हूं। जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो परोपकार का निस्वार्थ भाव ही मेरे काम का मुख्य आधार रहा है। हर दिन जागते ही मेरे मन में यही विचार आता है। हर जगह लोग मेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि मेरे मन में दूसरों का भला करने और सबके प्रति स्नेह रखने की भावना है।

'मैं ९१ साल का हूं, लेकिन मेरे सपनों के संकेतों से लगता है कि मैं शायद १३० साल तक जीवित रहूंगा। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि मैं बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए चीनी लोगों की मदद कर पाऊंगा और दुनिया भर के लोगों को एक अच्छा और सकारात्मक जीवन जीने में भी मदद कर सकूंगा। मैं यही करना चाहता हूं - धन्यवाद।'

परम पावन के भाषण का लद्दाखी अनुवादक ने लद्दाखी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद निर्वासित तिब्बती संसद की स्पीकर डोल्मा शेरिंग ने संसद का बयान पढ़कर सुनाया, जो इस प्रकार है-

'तिब्बत और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से निर्वासित तिब्बती संसद परम पावन महान १४वें दलाई लामा को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपार खुशी, श्रद्धा और आनंद का अनुभव करती है। वे करुणा की साक्षात मूरत, दुनिया के महान रक्षक और सभी प्राणियों के मित्र हैं। तिब्बती लोगों के लिए आपके अलावा कोई और शरणदाता, रक्षक या बचाव करने वाला नहीं है। आप ही हमारी उम्मीद, रक्षक और संरक्षक हैं। कृतज्ञता के भाव से हम प्रार्थना के ये शब्द अर्पित करते हैं:-

'सभी विजेताओं (बुद्धों) के महान कार्यों के क्षेत्र में, आप अकेले ही,

बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं,

आपने बिना किसी भेदभाव के इसे बनाए रखने,

संरक्षित करने और फैलाने में महारत हासिल की है,

हम मंजुश्री के साक्षात स्वरूप आपकी प्रार्थना करते हैं।

'कृतज्ञता के भाव से हमें तिब्बती लोगों के मकसद के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।'

'दुख-दर्द के अंधेरे में डूबी बर्फ की इस धरती पर,

आपकी करुणा की शानदार चमक

हमेशा राहत और भलाई का एहसास कराती रहती है।

आप हमेशा अडिग और दृढ़ बने रहें।'

एसओएस, टीसीवी स्कूल के छात्रों ने परम पावन (दलाई लामा) के जन्मदिन मनाने के क्रम में गाना गाया और नृत्य किया। अशरफ अली बार्च ने लेह और करगिल के मुस्लिम समुदायों की ओर से बधाई दी। मिफम ओत्सल के निर्देशन में लद्दाख थिएटर ऑर्गनाइजेशन ने अंगुलिमाल की कहानी पर आधारित एक छोटा नाटक पेश किया। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था, जिसने एक हजार इंसानों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाने का प्रण ले रखा था। बुद्ध का दर्शन होते ही वह धर्म के प्रभाव में आ गया और उसे समझ आया कि हिंसा से सफलता नहीं मिलती और करुणा ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं।

परम पावन ने लद्दाख के सभी समूहों के गाने-नृत्य और सोनम लिंग तिब्बती बस्ती के निवासियों की प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। सिंधु नदी की दूसरी ओर स्थित चुशोट गांव के लोगों की शुभ प्रस्तुति देखकर भी उन्हें खुशी हुई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, एलजीए के उपाध्यक्ष गेशे लोबसांग याशी ने प्रार्थना की कि परम पावन दीर्घायु हों। उन्होंने रिम्पोछे, संघ के सदस्यों, सिक्योंग और भारत सरकार के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज के समारोह की अध्यक्षता करने के लिए परम पावन का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'आपकी आवाज सुनकर हम खुशी से भर जाते हैं। जैसा कि बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, आप अवलोकितेश्वर हैं। बर्फ की यह धरती आपका ही निवास स्थान है। परम पावन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बार-बार लद्दाख आएं।'

उन्होंने भाषण देने वालों और मनोरंजक प्रस्तुतियां देने वालों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने इस अवसर को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया और अपनी बात इस प्रार्थना के साथ समाप्त की:-

हे महान पद्मपाणि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं:

आप वाणी पर अधिकार रखने वाले, अटूट और सौम्य गौरव हैं,

आपकी उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि का पात्र महान ज्ञान के अमृत से भरा है,

और आप धर्म के रक्षकों के विशाल और जीवंत सागर को

सुंदर आभूषणों से सजा रहे हैं!

इसके बाद परम पावन अपने निवास स्थान के लिए रवाना हो गए और पूरे रास्ते मुस्कुराते रहे। उनके जाने के बाद भी जश्न जारी रहा और पारंपरिक गीत 'हैप्पी बर्थडे टू यू...' को तिब्बती अनुवाद के साथ खुशी-खुशी गाया गया।'

◆ ०२. सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' को लेकर दुनिया भर से तत्काल अपील की

धर्मशाला। सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तिब्बती लोगों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से दुनिया भर की सरकारों, विदेश मंत्रालयों, सांसदों, थिंक टैंक और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आधिकारिक पत्र भेजकर और वर्चुअल माध्यमों से एक तत्काल अपील जारी की है। इस अपील में चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

०१ जुलाई, २०२६ से लागू इस कानून को बीजिंग राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के उपाय के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन असल में, यह कानून 'नस्लीय एकीकरण' के नाम पर तिब्बतियों और अन्य नस्लीय अल्पसंख्यकों की अलग भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान को कमजोर करके उन्हें मुख्यधारा में विलय करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक व्यापक कानूनी छलावा है।

अपनी अपील में, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने कहा है कि यह कानून लंबे समय से चली आ रही आत्मसात करने की नीतियों को कानूनी जामा पहनाता है। इसके तहत मंदारिन भाषा में शिक्षा को अनिवार्य करना, मिश्रित समुदायों को बनाने और विभिन्न नस्लों के बीच विवाहों के जरिए जनसांख्यिकीय बदलाव को बढ़ावा देना, सरकारी निगरानी का दायरा बढ़ाना और आलोचकों तथा विदेशों में तिब्बती समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए चीन के अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाने की चाल शामिल है। इस कानून को तिब्बती लोगों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सिक्योंग ने सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इस कानून का विरोध करें, इसे रद्द करने की मांग करें, इसके मानवाधिकार प्रभावों की अंतरराष्ट्रीय जांच का समर्थन करें, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएं और सार्थक बातचीत के जरिए चीन-तिब्बत विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयासों को फिर से तेज करें। यह पूरी अपील इस प्रकार है:-

'मैं तिब्बती लोगों के भविष्य और उनकी खास सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बचाने की गहरी चिंता और जरूरी मामले को लेकर आपसे अपील कर रहा हूं। ऐतिहासिक रूप से आजाद देश तिब्बत पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में अब भी एक अनसुलझा विवाद बना हुआ है।

१२ मार्च २०२६ को पीआरसी सरकार ने 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून' बनाया है, जो ०१ जुलाई २०२६ से लागू होने वाला है। हालांकि चीनी अधिकारी इस कानून को 'सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता' को बढ़ावा देने वाले तरीके के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन असल में यह जबरन आत्मसात करने (यानी अपनी संस्कृति में विलय करने) की नीतियों को अमली जामा पहनाता है। चीन सरकार द्वारा सरकारी औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के विस्तार और तिब्बती भाषा, धर्म, शिक्षा और पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित करने वाली अन्य

नीतियों के साथ अगर मौजूदा कानूनों-नियमों को मिलाकर देखा जाए, तो यह कानून तिब्बती पहचान के लंबे समय तक बने रहने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है और यह जनसंहार की दिशा में एक और कदम हो सकता है।'

क. आत्मसात करने के उपकरण : यह कानून तिब्बती पहचान को कैसे खत्म करता है

नया कानून जमीनी स्तर के प्रशासन से लेकर हमारे स्कूलों, समुदायों तक तिब्बती पहचान को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए दूरगामी शासनादेशों को लागू करता है। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:-

· अनिवार्य मंदारिन: इस कानून का मूल तत्व है कि स्कूल प्री-किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक शिक्षा की प्राथमिक भाषा के रूप में मंदारिन चीनी का उपयोग करें। यह नीति सीधे तौर पर युवा पीढ़ी को लक्ष्य करने वाला है। इससे धीरे-धीरे युवाओं के व्यावहारिक मूल्य और रोजमर्रा की जिंदगी में तिब्बती भाषा की प्रासंगिकता खत्म हो रही है।

· समुदायों को तोड़ना और जनसांख्यिकी कमजोर करना: यह कानून 'पारस्परिक रूप से अंतर्निहित सामुदायिक वातावरण' निर्माण करने की बात करता है। इस तरह का वातावरण ऐतिहासिक रूप से हमारी संस्कृति को जीवित रखने वाले पारंपरिक तिब्बती परिक्षेत्रों में मिश्रित-नस्लीय समूहों की घुसपैठ और पड़ोसी बनाने की प्रवृत्ति को आक्रामक रूप से प्रोत्साहित करता है। तिब्बतियों और गैर-तिब्बतियों के बीच 'अंतर-नस्लीय' विवाहों को बढ़ावा देने वाली नीति भी इन्हीं प्रावधानों के साथ जुड़ी हुई है। यह कानून तिब्बती किसानों और खानाबदोशों को उनकी पैतृक भूमि से जबरन विस्थापित करते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से समुदाय को कमजोर कर उनकी विशिष्ट तिब्बती पहचान को खत्म करने का राज्य-प्रायोजित प्रयास है।

· अधिनायकवादी निगरानी और नियंत्रण: 'सामाजिक शासन' के बैनर तले यह कानून तिब्बती मामलों के सभी पहलुओं पर कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण का विस्तार करता है और कथित 'प्रमुख खतरों' की पहचान और प्रबंधन के लिए 'वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन' के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। व्यवहार में, इस व्यापक और अस्पष्ट आदेश का उपयोग तिब्बतियों की अपनी आस्था का पालन करने, अपनी भाषा बोलने या अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसी सामान्य गतिविधियों की गहन निगरानी को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है।

· अंतरराष्ट्रीय दमन: इस कानून का अनुच्छेद- ६३ 'नस्लीय एकीकरण को कमजोर करने' के आरोपी किसी भी व्यक्ति पर अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जिससे चीन के बाहर के व्यक्तियों पर संभावित आपराधिक मुकदमा चल सकता है। बीजिंग के अधिकार क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमाओं से परे जाकर, इन प्रावधानों के आलोचकों, अधिवक्ताओं और निर्वासित तिब्बती सदस्यों को चुप कराने के लिए एक शक्तिशाली साधन बनने का खतरा मोल लेता है। इसकी व्यापक और अस्पष्ट भाषा चीनी अधिकारियों को विदेशी नागरिकों- जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, विशेषकर तिब्बती मूल के लोगों को निशाना बनाने का व्यापक अधिकार देती है। १६ अप्रैल २०२६ को संयुक्त राष्ट्र के आठ मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कानून पर चिंता जताई, विशेष रूप से चेतावनी दी कि अनुच्छेद- ६३ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर दमन करने की इजाजत दे सकता है और चीन की सीमाओं से परे मौलिक अधिकारों को खतरे में डाल सकता है।

ख. तिब्बत के लिए विनाशकारी

इस कानून के परिणाम हम तिब्बती लोगों के लिए विनाशकारी हैं। यह सार्थक क्षेत्रीय स्वायत्तता के मूल संवैधानिक वादे पर एक घातक प्रहार की तरह है।

कानूनी रूप से दमन: 'कानून के शासन' के नाम पर पीआरसी ऐसी नीतियां बना रहा है, जो उन स्वायत्तता वाले अधिकारों को कमजोर करती हैं, जिनकी रक्षा का उसने औपचारिक रूप से वादा किया था। यह राजनीतिक नियंत्रण और आत्मसातीकरण को कानूनी जवाबदेही में बदल रहा है।

तिब्बतियों को उनकी विरासत और जड़ों से अलग करना: अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आबादी के स्थानांतरण को बढ़ावा देने वाली और तिब्बती भाषा को हाशिए पर धकेलने वाली नीतियों से चीनी सरकार व्यवस्थित रूप से तिब्बतियों को उनकी पैतृक भूमि, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं से अलग कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल एकीकरण नहीं, बल्कि धीरे-धीरे एक अलग तिब्बती पहचान को राज्य द्वारा परिभाषित 'चीनी राष्ट्र (झोंगहुआ मिन्जू)' के प्रति निष्ठा से बदलना है।

तिब्बती पहचान को अपराध की श्रेणी में डालना: यह कानून आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को 'चीनी राष्ट्र के लिए समुदाय की मजबूत भावना बनाने' की नीति से जोड़ता है। तिब्बती धार्मिक प्रथाओं, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण को 'अलगाववाद' के रूप में पेश करके यह एक ऐसा ढांचा बनाता है, जिसमें एक अलग तिब्बती पहचान को व्यक्त करने को राजनीतिक अपराध माना जा सकता है।

ग. तत्काल कार्रवाई की अपील

तिब्बती लोगों की नजर में इस कानून की कोई नैतिक वैधता नहीं है। अपनी मातृभाषा, धर्म, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को बचाए रखना एक बुनियादी मानवाधिकार है। हालांकि यूरोपीय संसद और संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून के असर को लेकर पहले ही गंभीर चिंताएं जताई हैं, फिर भी और मजबूत तथा निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, हम आपकी सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सम्मानपूर्वक अपील करते हैं कि वे हमारा अनुरोध सुनें और निम्नलिखित कदम उठाएं:-

- विरोध करें, अस्वीकार करें और इसे रद्द करने की मांग करें: हम आग्रह करते हैं कि आप चीनी सरकार से इस कानून के प्रति अपना कड़ा विरोध औपचारिक रूप से जताएं, इसके लागू होने को अस्वीकार करें और इसे रद्द करने की मांग करें।

- संयुक्त राष्ट्र से जांच शुरू कराएं: संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और तंत्रों को पत्र भेजें कि वे चीन की आत्मसातीकरण नीतियों की तत्काल समीक्षा करें और सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक अधिकारों के आगे और उल्लंघन

को रोकने के लिए सभी उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साधनों का उपयोग करें।

- दोषियों को जवाबदेह ठहराएं: अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से, इन नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थानों की व्यापक जांच करें और उनको प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों सहित जवाबदेही तय करने वाले उचित उपायों के इस्तेमाल पर विचार करें।

- सार्थक बातचीत पर जोर दें: बीजिंग पर एकजुट राजनयिक दबाव डालें, ताकि चीन-तिब्बत विवाद को सच्ची और आपसी सम्मान वाली बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।

- हमारा समर्थन करें: निर्वासन में तिब्बती संस्कृति और पहचान को बचाने और बढ़ावा देने के लिए निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रयासों का समर्थन करें, साथ ही तिब्बत में तिब्बती पहचान को जान-बूझकर मिटाने की कोशिशों को उजागर करें और उनका विरोध करें।

◆ ०३. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर लोबगा रंगजेन के आत्मदाह पर सिक्योंग पेन्पा शेरिंग का आधिकारिक बयान

०३ जुलाई, २०२६

धर्मशाला। आज ०३ जुलाई को जारी एक लिखित बयान में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने ०२ जुलाई, २०२६ को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने तिब्बती आंदोलनकारी लोबगा रंगजेन (लोबसांग पाल्डेन) के आत्मदाह पर गहरा दुख व्यक्त किया। घटना से कुछ घंटे पहले जारी एक वीडियो संदेश में लोबगा ने कहा था कि उनका यह अंतिम बलिदान तिब्बत के राष्ट्रीय मुद्दे के समर्थन में है।

सिक्योंग ने लिखा, 'हालांकि हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी कीमती है और तिब्बत के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष की सेवा के लिए इसे बचाकर रखना जरूरी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की ओर से, मैं सभी तिब्बती भाइयों-बहनों से पुरजोर अपील करता हूं कि वे अपनी जिंदगी की कद्र करें। तिब्बत के अंदर हो रहे जनसंहार और ०१ जुलाई से लागू किए गए कठोर 'नस्लीय एकीकरण एवं प्रगति कानून' ने ही लोबगा रंगजेन को इस दुखद फैसले के लिए मजबूर किया। वह तिब्बत के उन कम से कम १५७ तिब्बतियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने चीनी शासन के क्रूर दमन की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अपनी जान दे दी है।'

सिक्योंग ने लोबगा रंगजेन के परिवार, दोस्तों और पूरे तिब्बती समुदाय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से, उन्होंने गंभीरता से संकल्प लिया कि तिब्बती इन बलिदानों की भावना को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करेंगे कि ये बलिदान बेकार न जाएं।

सिक्योंग ने निर्वासित तिब्बतियों, दुनिया भर की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से भी तत्काल अपील की है कि वे तिब्बत के अंदर के संकट की गंभीरता को समझें, आगे आएं और तिब्बती इतिहास के इस अहम मोड़ पर अपनी आवाज उठाएं।

◆ ०४. सीटीए ने आत्मदाह करने वाले तिब्बती लोबसांग पाल्डेन की शहादत के सम्मान में प्रार्थना सभा आयोजित की

०३ जुलाई, २०२६

धर्मशाला। लोबसांग पाल्डेन (जिन्हें लोबगा रंगजेन भी कहा जाता था) नाम के एक ५२ वर्षीय तिब्बती आंदोलनकारी ने गत ०२ जुलाई की शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसे चीन की तिब्बत में लगातार दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आखिरी कदम माना जा रहा है। यह विरोध तथाकथित 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति' कानून के लागू होने के बाद किया गया, जो एक दिन पहले ही लागू हुआ था।

उनकी शहादत के सम्मान में, दुनिया भर के तिब्बतियों ने श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं। इसी तरह, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में उसके सभी कर्मचारियों ने आज शाम सिक्योंग हॉल में उनके बलिदान के सम्मान में प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मूल रूप से तिब्बत के रहने वाले लोबगा लगभग दो दशक पहले चीनी शासन से बचकर निकल आए थे और अमेरिका में अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी। निर्वासन के दौरान, वे तिब्बत के मुद्दे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे और लगातार तिब्बत की आजादी और तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों की बहाली की वकालत करते रहे।

आत्मदाह करने से पहले लोबगा ने एक आखिरी वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने तिब्बत के अंदर बिगड़ते हालात पर गहरा दुख व्यक्त किया था। उन्होंने अपने आखिरी संदेश में कहा है, 'मैं निर्वासित तिब्बतियों से कहना चाहता हूं कि बिना कोशिश के कोई भी बड़ा राष्ट्रीय मकसद हासिल नहीं होता, कुछ भी अपने-आप नहीं मिलता। इसलिए, हमें यह समझना होगा कि अपनी साझा लड़ाई के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी।

हम परम पावन दलाई लामा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए निर्वासन में एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। हममें से कुछ लोगों की शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद, परम पावन ने इस लोकतांत्रिक ढांचे को लागू किया और बनाए रखा। इसका मकसद कभी भी बंटवारा करना नहीं था, बल्कि तिब्बती लोगों और राष्ट्र की सामूहिक भलाई को

आगे बढ़ाना था।

परम पावन ने हमें यह भी याद दिलाया है कि निर्वासित तिब्बतियों को, खासकर यूरोप और अमेरिका में रहने वालों को, आरामतलब नहीं हो जाना चाहिए। हम तिब्बती लोगों के प्रतिनिधि हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी लगन और मेहनत से उनके मुद्दे के लिए काम करें।

सभी तिब्बतियों ने, चाहे वे ऊ-त्सांग, खाम या अमदो में से किसी भी प्रांत के हों, चीन की दमनकारी नीतियों के कारण एक जैसा दुख सहा है।

आज, हमारे लोगों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं। यह तिब्बत की आजादी छिन जाने का नतीजा है। इसलिए, एकता बहुत जरूरी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, निर्वासित तिब्बती संसद और सभी तिब्बतियों को तिब्बत के मुद्दे के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।

हमें इलाके या पंथ के आधार पर मतभेदों को भुला देना चाहिए और तिब्बत की सेवा करने के एकमात्र मकसद पर ध्यान देना चाहिए। 'हमारी आजादी कभी थी, वह खो गई और उसे वापस पाने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है।'

हम अगली ही सप्ताह परम पावन (दलाई लामा) के ९१वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जश्न मनाने जा रहे हैं। यह जश्न खुशी और गरिमापूर्ण होना चाहिए। गीत और नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का स्वागत है। हालांकि, जश्न से परे, हममें से प्रत्येक को तिब्बती मुद्दे के प्रति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए।

मेरी अपील सरल है, 'यदि मैं आंदोलन में गंभीर रूप से सक्रिय होता हूं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरे पास भोजन या कपड़ों की कमी है और न ही किसी व्यक्तिगत कठिनाई है। मैं यह तिब्बत की खातिर करता हूं। इसी तरह हर किसी को तिब्बत के लिए जो कुछ भी वे कर सकते हैं, उसमें योगदान देना जारी रखना चाहिए।'

अपने एक अन्य वीडियो में, आत्मदाह से कुछ क्षण पहले, लोबगा शांति से पारंपरिक तिब्बती पोशाक (चुपा) पहने और तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पास पहुंचे।

उनकी शहादत ने एक बार फिर तिब्बत में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। २००९ से, तिब्बत के भीतर कुल १५८ तिब्बतियों ने स्वतंत्रता और न्याय के लिए आत्मदाह किया है। इसके अलावा, निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के बीच भी आत्मदाह की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे हालिया मामला लोबगा का है, जो इस संघर्ष के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) में एक प्रार्थना सभा के दौरान, धर्म और संस्कृति विभाग के कलोन (मंत्री) और कार्यवाहक सिक्योंग शेग्याल चुक्या द्रानी ने सभी तिब्बतियों से आत्मदाह जैसे चरम कदम उठाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा, 'जिन लोगों ने आत्मदाह किया है, वे हमारे मुद्दे के लिए एक अपूरणीय क्षति हैं।'

अपने आधिकारिक बयान में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने भी लोबगा की शहादत पर शोक व्यक्त किया और लिखा, 'हालांकि हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं, लेकिन मानव जीवन अनमोल है और तिब्बत के लिए दीर्घकालिक संघर्ष की सेवा के लिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की ओर से, मैं सभी साथी तिब्बतियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने जीवन को संजोकर रखें। तिब्बत के भीतर हो रहे जनसंहार और ०१ जुलाई से बर्बर 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून (एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ)' के लागू होने के कारण ही लोबगा रंगजेन ने यह दुखद निर्णय लिया।' वे तिब्बत के उन कम से कम १५८ तिब्बतियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने चीनी शासन के तहत हो रहे क्रूर दमन की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अपनी जान दे दी।'

सिक्योंग ने लोबगा रंगजेन के परिवार, दोस्तों और पूरे तिब्बती समुदाय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से, उन्होंने पूरे संकल्प के साथ यह वादा किया कि तिब्बती इन बलिदानों की भावना को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करेंगे कि ये बलिदान व्यर्थ न जाएं।'

◆ ०५. धर्मशाला में सीटीए और तिब्बतियों ने परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन मनाया

०६ जुलाई, २०२६

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) और धर्मशाला में रहने वाले तिब्बतियों ने धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर त्सुगलाखंग के प्रांगण में परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सैकड़ों तिब्बती और परम पावन के अनुयायी इकट्ठा हुए।

इस समारोह में कांगड़ा जिले के उपायुक्त श्री हेमराज बैरवा (आईएएस) मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेता भी मौजूद थे, जिनमें कलोन (मंत्री), तिब्बती सांसद, सीटीए के तहत स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुख, तिब्बती गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और आम जनता शामिल थी।

इस समारोह में विदेशी गणमान्य व्यक्ति और मेहमान भी शामिल हुए, साथ ही स्थानीय भारतीय समुदाय के लोग और पर्यटक भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद इस खास मौके पर जन्मदिन का केक काटा गया।

अपने संबोधन में, उपायुक्त श्री बैरवा ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से परम पावन दलाई लामा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने शांति, करुणा, अहिंसा और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के समर्पण को नमन किया। उन्होंने 'करुणा वर्ष' थीम के तहत पूरे साल कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भी बधाई दी।

उन्होंने दुनिया के लिए परम पावन के चार मुख्य प्रतिबद्धताओं के माध्यम से उनके अमूल्य योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा, 'परम पावन सिर्फ एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता नहीं हैं, वे संघर्ष और बिखराव से बंटी दुनिया में शांति, करुणा और सार्वभौमिक जिम्मेदारी के जीवंत प्रतीक हैं। ऐसे समय में, जब तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवता में बिखराव और दूरियां बढ़ रही हैं, परम पावन का जीवन सद्भाव का असाधारण मिसाल पेश करता है। उन्होंने हमें हमेशा दिखाया है कि खुशी का असली स्रोत भौतिक धन या सत्ता में नहीं, बल्कि एक स्नेहपूर्ण हृदय विकसित करने, क्षमा की साधना और मानवीय प्रेम को बढ़ावा देने में है।'

उपायुक्त ने कहा कि एक जनसेवक के तौर पर, उन्हें आम जनता की सेवा करने में परम पावन का संदेश और मार्गदर्शन विशेष रूप से प्रासंगिक और प्रेरणादायक लगता है।

मुख्य अतिथि ने इस क्षेत्र में तिब्बती समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने धर्मशाला में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने में तिब्बती समुदाय के अहम योगदान के लिए कांगड़ा के लोगों की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

इसके बाद, निर्वासित तिब्बती संसद के डिप्टी स्पीकर खेन्पो सोनम टेनफेल ने संसद का वक्तव्य पढ़ा, जबकि कार्यवाहक सिक्योंग और धर्म व संस्कृति विभाग के कलोन, सेग्याल चुक्या ड्रानी ने सभा के सामने कशाग का वक्तव्य पढ़ा।

आधिकारिक समारोह में तिब्बती स्कूलों, तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकारों और तिब्बती संस्थाओं व संगठनों के समूहों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जो तिब्बत की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाती थीं। इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्सव का माहौल बना दिया और साथ ही अपनी पहचान पर बढ़ते खतरों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समुदाय की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाया।

समारोह में सीटीए के कई सरकारी अधिकारियों को अपने- अपने विभागों में समर्पित सेवा और बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

समारोह का समापन सेंट्रल घोटोन आयोजन समिति के उपाध्यक्ष और सचिव थुप्टेन शेरिंग के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। परम पावन १४वें दलाई लामा के ९१वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुनिया भर में तिब्बती समुदायों और समर्थकों द्वारा इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए।

◆ ०६. आईटीसीओ और हिमालयी परिवार ने नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा का ९१वां जन्मदिन मनाया

०८ जुलाई, २०२६

नई दिल्ली। भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) और हिमालयी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में परम पावन १४वें दलाई लामा की ९१वीं जयंती बड़े धूमधाम और सम्मान के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित वक्ता शामिल हुए, जिनमें दिल्ली स्टडी ग्रुप्स के अध्यक्ष विजय जॉली, सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. के. खिरमे, माननीय सांसद श्री तापिर गाओ, प्रोफेसर डॉ. शाहिद अख्तर, माननीय डॉ. इंद्रेश कुमार और परम पावन दलाई लामा के कार्यालय (ब्यूरो) के प्रतिनिधि प्रमुख थे। कार्यक्रम में तिब्बत समर्थक समूहों, सामाजिक संगठनों, विद्वानों, पत्रकारों, तिब्बत समर्थकों और तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर परम पावन के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान करने के साथ-साथ तिब्बती लोगों के साथ उनकी पहचान, संस्कृति, धर्म और मानवाधिकारों को बचाने के उनके शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति एकजुटता दोहराई गई।

कार्यक्रम की शुरुआत भारत-तिब्बत के लोगों के बीच गहरी दोस्ती और साझा मूल्यों के प्रतीक के रूप में भारत और तिब्बत के राष्ट्रगान के साथ हुई।

इसके बाद मंच पर मौजूद प्रतिष्ठित अतिथियों द्वारा औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित किया गया और साथ ही श्रीमती अनीता शुक्ला द्वारा शांति, ज्ञान और सार्वभौमिक सद्भाव की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ किया गया।

इसके बाद सभा ने तिब्बती और भारतीय शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा। हिमालयी परिवार के स्वर्गीय श्री भुवन भट्ट और स्वर्गीय लोबगा रंगजेन को भी श्रद्धांजलि दी गई। लोबगा रंगजेन ने चीन सरकार के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' के विरोध में गत ०२ जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया था।

श्रद्धांजलि के बाद, मंच पर मौजूद प्रतिष्ठित अतिथियों को तिब्बती मुद्दे और जनसेवा में उनके योगदान के लिए प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया गया।

समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा प्रस्तुत सामूहिक गीत के साथ हुई, जिसमें शांति, एकता और करुणा की भावना झलक रही थी। इसके बाद, १४वें दलाई लामा के सम्मान में एक विशेष उत्सव गीत प्रस्तुत किया गया, जिसे गजल और हल्के संगीत (लाइट म्यूजिक) के साथ राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता श्री इंदरजीत सिंह ने बहुत ही खूबसूरती से गाया।

इसके बाद मशहूर लोक गायिका सुश्री ऋचा शर्मा ने एक शानदार हिमाचली लोकगीत प्रस्तुत किया। इस गीत में हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का गुणगान किया गया है, जो हिमालयी समुदायों

व तिब्बत के बीच अटूट रिश्ते का प्रतीक है।

कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 'हिमालयी परिवार' के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र कंसल द्वारा गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों, तिब्बत समर्थन समूहों के सदस्यों और प्रतिभागियों के स्वागत करने और उनका परिचय देने के साथ हुई। उन्होंने सहयोग बढ़ाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए 'हिमालयी परिवार' जैसे साझा मंच के तहत तिब्बत के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तिब्बत में चीन की नीतियों को अमानवीय बताकर निंदा की और इस विश्वास को दोहराया कि 'तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक आजाद तिब्बत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। उन्होंने वैश्विक समुदाय से तिब्बत के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और लोकतांत्रिक दबाव बनाने का आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त की।

नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा के कार्यालय (ब्यूरो) के प्रतिनिधि जिग्मे जुंगने ने परम पावन दलाई लामा, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के तिब्बतियों की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं और हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने छह दशकों से अधिक समय से तिब्बतियों को शरण, करुणा और अटूट समर्थन देने के लिए भारत सरकार और यहां के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने याद दिलाया कि परम पावन को अहिंसा और शांतिपूर्ण बातचीत के प्रति उनके आजीवन समर्पण के सम्मान में १९८९ में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने परम पावन की चार मुख्य प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया, जो इस प्रकार है-: 'सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, तिब्बती लोगों के कल्याण की रक्षा करना और भारत के प्राचीन बौद्ध ज्ञान को पुनर्जीवित करना।' उन्होंने सभा को यह भी बताया कि हाल ही में परम पावन के घुटने की सफल सर्जरी हुई है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने, लंबी उम्र और निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अपने संबोधन के समापन पर, उन्होंने तिब्बती समुदाय के इस विश्वास को दोहराया कि भारत तिब्बत के मुद्दे का समर्थन तब तक जारी रखेगा, जब तक उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो जातीं।

'कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया' के राष्ट्रीय समन्वयक श्री आर. के. खिरमे ने अपने संबोधन की शुरुआत परम पावन (दलाई लामा) की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए और उन्हें करुणा और मानवता का वैश्विक प्रतीक बताते हुए की। उन्होंने १९५९ में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में परम पावन की यात्रा से जुड़ी उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे खिनजेमाने में परम पावन द्वारा छोड़ी गई छड़ी एक पवित्र पेड़ बन गई और कैसे उनकी यात्रा के दौरान लगाया गया एक और पौधा पवित्र तीर्थस्थल बन गया है। उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए भविष्य के तीर्थयात्रा कार्यक्रमों में इन जगहों को शामिल करें। मौजूदा हालात पर बात करते हुए, उन्होंने भाष और संस्कृति को आत्मसात कर जाने वाले चीनी कानूनों, खासकर स्कूलों में तिब्बती भाषा की जगह मंदारिन को थोपे जाने पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम तिब्बत की अनूठी पहचान के लिए खतरा हैं और घोषणा की कि पूरे भारत में तिब्बत समर्थक समूह इन नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण जागरूकता अभियान तेज करेंगे। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए सभी को परम पावन के उपदेशों का पालन करने और तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रोफेसर डॉ. शाहिद अख्तर ने कार्यक्रम में शामिल सभी संगठनों को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि दलाई लामा की विचारधारा करुणा, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देकर धर्म से परे है। उन्होंने कहा कि १९५९ के बाद भारत तिब्बती समुदाय का आध्यात्मिक घर बन गया और इसने तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं को संजोकर रखा है। भारत की सभ्यतागत विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश अपने यहां आए शरणार्थियों को शरण देता है, उनका सम्मान करता है और उनकी रक्षा करता है। उन्होंने युवाओं और छात्रों से परम पावन के उपदेशों का अध्ययन करने और तिब्बत के समर्थन में शांतिपूर्ण अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य के दलाई लामा को मान्यता देने का अधिकार पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध परंपराओं के पास है, न कि किसी बाहरी राजनीतिक सत्ता के पास। उन्होंने सभी संगठनों और नागरिकों को तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन को मजबूत करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी के साथ अपने संबोधन का समापन किया।

माननीय सांसद श्री तापिर गाओ ने सभा का अभिनंदन किया और तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे सम्मानित परंपराओं में से एक, दलाई लामा की संस्था पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले दलाई लामा का चयन पूरी तरह से तिब्बती धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए और इस पवित्र प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। भारत के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश के नजरिए से बात करते हुए, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तिब्बत के रणनीतिक महत्व को समझाया और भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावों पर चिंता जताई। उन्होंने तिब्बती भाषा, शिक्षा, धर्म और संस्कृति पर रोक लगाने वाले चीन के हालिया कानूनों की ओर भी ध्यान दिलाया और इसे बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने लोकतांत्रिक देशों से इन नीतियों की सामूहिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया और युवा तिब्बतियों व भारतीयों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि लगातार शांतिपूर्ण प्रयासों से आखिरकार तिब्बत के मुद्दे को मजबूती मिलेगी।

माननीय डॉ. इंद्रेश कुमार ने अपने मुख्य भाषण में परम पावन दलाई लामा से अपनी मुलाकात के निजी अनुभव साझा किए और भारत की आध्यात्मिक विरासत और तिब्बत के भविष्य पर हुई चर्चाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि परम पावन दलाई लामा भारत को तिब्बत का आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और उनका मानना है कि शांति, करुणा और अहिंसा की भारतीय विचारधारा पूरी दुनिया को उम्मीद देती है। इतिहास पर नजर डालते हुए, डॉ. इंद्रेश ने कहा कि तिब्बत पारंपरिक रूप से भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच रहा है और इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत में होने वाले घटनाक्रम सीधे तौर पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उन्होंने चीन की विस्तारवादी सोच के बारे में ऐतिहासिक चेतावनियों का भी जिक्र किया और जन-जागरुकता,

शांतिपूर्ण पक्षधरता अभियान और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। तिब्बत का समर्थन करने वाले कई संगठनों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों से लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों से जागरुकता अभियान चलाते रहने का आग्रह किया। उन्होंने यह विश्वास जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि अंततः सत्य, करुणा और दृढ़ता की जीत होगी और तिब्बती लोगों की आकांक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहेंगी।

कार्यक्रम के अंत में, माननीय डॉ. इंद्रेश कुमार जी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए भाग लेने वाले कलाकारों और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र समूह को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया और आशीर्वाद प्रदान किए। श्री इंद्रजीत सिंह, सुश्री ऋचा शर्मा, श्री राजेश बजाज और श्री भूपेंद्र कंसल सहित विशिष्ट योगदानकर्ताओं को भी उनके बहुमूल्य सहयोग और भागीदारी के लिए सम्मान-चिह्न भेंट किए गए।

इस अवसर पर, श्री जिग्मे जुंगने ने गणमान्य व्यक्तियों और वक्ताओं को चीनी शोधकर्ता माननीय शिंग लाओ द्वारा लिखित पुस्तक 'तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट ऑफ चाइना सिंस एंटीक्विटी (तिब्बत प्राचीन काल से कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था) भेंट की, जिसमें तिब्बत की स्वतंत्र विरासत के ऐतिहासिक प्रमाणों पर प्रकाश डाला गया है।

इसके बाद हिमालयी परिवार के राष्ट्रीय सचिव श्री ऋषि वालिया ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मुख्य अतिथि, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं, कलाकारों, मीडिया कर्मियों और कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने में पूरे दिल से सहयोग देने वाले सभी उपस्थित लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

'कोर ग्रुप फॉर तिब्बती कॉज- इंडिया' ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तिब्बत में तथाकथित 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' को लागू करने की कड़ी निंदा की। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कानून तिब्बती लोगों की पहचान, संस्कृति, भाषा और धार्मिक विरासत को कमजोर करता है। परम पावन १४वें दलाई लामा की ९१वीं जयंती के उपलक्ष्य में केक काटने का एक समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह उनके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और मानवता के लिए निरंतर मार्गदर्शन की प्रार्थना का प्रतीक था।

कार्यक्रम का समापन 'हाई टी (चाय-नाश्ते)' के साथ हुआ।

- आईटीसीओ की रिपोर्ट

◆ ०७. बेल्जियम के विदेश मंत्री ने कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकार पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध समुदाय का मामला है

०६ जुलाई, २०२६

ब्रसेल्स, ०५ जुलाई। बेल्जियम के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, यूरोपीय मामलों और विकास सहयोग मामलों के मंत्री मैक्सिम प्रेवोट ने फिर से कहा कि परम पावन दलाई लामा का उत्तराधिकार पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध समुदाय का मामला है और यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संपन्न होना चाहिए।

यह वक्तव्य बेल्जियम की संघीय संसद की सदस्य एल्स वैन हूफ द्वारा विदेश मामलों की समिति की १७ जून की बैठक में पूछे गए एक मौखिक सवाल के जवाब में आया। यह सवाल भविष्य के दलाई लामा की पहचान करने में चीन के दखल की कोशिशों और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों पर हाल ही में लागू किए गए 'नस्लीय एकीकरण कानून' के असर के बारे में था।

अपनी बात रखते हुए, सांसद वैन हूफ ने चीनी सरकार द्वारा बार-बार दिए गए बयानों पर गहरी चिंता जताई, जिनमें परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान को नियंत्रित करने के इरादे की बात कही गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि बीजिंग द्वारा अपना उम्मीदवार नियुक्त करने की कोई भी कोशिश सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध परंपराओं और धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगी। इस अधिकार में धार्मिक समुदायों को अपनी स्थापित रीति-रिवाजों के अनुसार अपने आध्यात्मिक नेताओं को चुनने का अधिकार भी शामिल है।

चीन द्वारा गत ०१ जुलाई से लागू किए नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' का जिक्र करते हुए सांसद वैन हूफ ने कहा कि यह कानून तिब्बतियों और अन्य नस्लीय समुदायों के प्रति लंबे समय से चली आ रही आत्मसात करने की नीतियों को और अधिक औपचारिक बनाता है। उन्होंने पूछा कि क्या बेल्जियम इस बात से सहमत है कि १५वें दलाई लामा की पहचान पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार होनी चाहिए और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों पर नए कानून के असर से निपटने के लिए बेल्जियम क्या कदम उठाएगा (जिसमें यूरोपीय संघ के स्तर पर उठाए जाने वाले कदम भी शामिल हैं)।

बेल्जियम सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री प्रेवोट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'दलाई लामा का उत्तराधिकार तिब्बती समुदाय का अपना धार्मिक मामला है, जिसमें किसी नास्तिक सरकार और अधिकारियों का कोई दखल नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति, धर्म की स्वतंत्रता और तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर जताई गई चिंताओं से सहमत हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि बेल्जियम चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत में तिब्बत की स्थिति का मुद्दा लगातार उठाता रहा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल २०२६ में चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर बात की थी और मार्च में हुई द्विपक्षीय

राजनीतिक बातचीत के दौरान भी तिब्बत पर चर्चा हुई थी।

बेल्जियम के मानवाधिकारों से जुड़े व्यापक प्रयासों का जिक्र करते हुए मंत्री प्रेवोट ने याद दिलाया कि २०२४ में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन की 'यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (वैश्विक आवधिक समीक्षा)' के दौरान, बेल्जियम ने तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए सुझाव दिए थे। साथ ही, उन्होंने चीन से आग्रह किया कि वह धर्म की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा तिब्बत दौरे के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म की स्वतंत्रता और तिब्बत की स्थिति समेत मानवाधिकार यूरोपीय संघ और चीन के बीच संबंधों का एक अहम हिस्सा हैं। इन मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत, ईयू-चीन मानवाधिकार वार्ता और बहुपक्षीय मंचों पर लगातार चर्चा होती रहती है।

अपनी बात खत्म करते हुए, मंत्री प्रेवोट ने संसद को भरोसा दिलाया कि बेल्जियम हालात पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगा।

अपनी समापन टिप्पणी में, सांसद वैन हूफ ने मंत्री के स्पष्ट रुख का स्वागत किया और तिब्बत पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि तिब्बती लोगों के 'भुला दिए जाने' का खतरा है, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार पाबंदियां बढ़ रही हैं। परम पावन दलाई लामा के आने वाले जन्मदिन का जिक्र करते हुए, उन्होंने फिर से कहा कि तिब्बती लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगले दलाई लामा को पहचानने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही, उन्होंने चीन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को लगातार उठाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया।

मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए ब्रुसेल्स स्थित 'तिब्बत कार्यालय' की प्रतिनिधि रिग्जिन गेनखांग ने बेल्जियम सरकार का दिल से आभार जताया। उन्होंने सरकार के उस सैद्धांतिक रुख को फिर से दोहराने के लिए धन्यवाद दिया, जिसके अनुसार परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध समुदाय का मामला है। यह पहचान सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के अनुसार की जानी चाहिए और इसमें धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों का कोई दखल नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मंत्री प्रेवोट का स्पष्ट और दो-टूक रुख धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बती बौद्ध समुदाय के अपने आध्यात्मिक नेतृत्व को तय करने के मौलिक अधिकार के बचाव में एक अहम संदेश देता है। ऐसे समय में जब चीनी दखलंदाजी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, बेल्जियम का यह रुख मानवाधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है।'

प्रतिनिधि गेनखांग ने संसद में यह मुद्दा उठाने और तिब्बती लोगों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध रहने के लिए सांसद एल्स वैन हूफ का भी धन्यवाद किया। उन्होंने भरोसा जताया कि बेल्जियम इन सिद्धांतों को बनाए रखने और तिब्बती लोगों के बुनियादी अधिकारों का समर्थन करने के लिए अपने यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

- तब्बित कार्यालय, ब्रुसेल्स की रिपोर्ट

◆ ०८. चीन के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति' कानून को लेकर एस्टोनियाई संसद में तिब्बत समर्थक समूह और रीगिकोगु (एस्टोनियाई संसद) के सदस्यों का वक्तव्य

०९ जुलाई, २०२६

धर्मशाला। परम पावन दलाई लामा के ९१वें जन्मदिन के मौके पर, एस्टोनियाई संसद (रीगिकोगु) में तिब्बत समर्थक समूह के प्रमुख जुकु-काले रेड के नेतृत्व में सांसदों ने तिब्बत के प्रति एकजुटता दिखाते हुए और चीन (पीआरसी) के नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' की निंदा करते हुए कड़ा बयान जारी किया।

इस बयान पर रीगिकोगु के १०१ में से ५१ सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो अपने आप में बहुमत है। हालांकि, यह एक प्रतीकात्मक बहुमत है, जो तिब्बत के लिए व्यापक संसदीय समर्थन को जाहिर करता है।

एस्टोनियाई संसद ने लगातार तिब्बत मुद्दे का समर्थन किया है और एकजुटता दिखाई है, साथ ही तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति तथा चीन के कब्जे के बाद किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर चिंताएं जताई हैं। एस्टोनियाई सांसदों के साथ का यह लगातार संपर्क उनके सैद्धांतिक रुख और एस्टोनिया व तिब्बत के लोगों के बीच एकजुटता को दर्शाता है।

सालों से, एस्टोनियाई सांसदों ने विभिन्न पहलों के जरिए तिब्बती मुद्दे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें धर्मशाला की यात्राएं भी शामिल हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ बातचीत की और परम पावन दलाई लामा से मुलाकात की।

चीन के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' पर एस्टोनियाई संसद में तिब्बत समर्थक समूह और एस्टोनिया की संसद (रीगिकोगु) के सदस्यों का बयान

तिब्बत अब भी अनसुलझे अंतरराष्ट्रीय विवादों का विषय बना हुआ है। यह ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र देश था, जिस पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने जबरन कब्जा कर लिया था। गत १२ मार्च को, पीआरसी ने नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया और इसे ०१ जुलाई से लागू कर दिया है।

यह नया कानून तिब्बती पहचान को खत्म कर देगा और ऐसे दूरगामी नियम लागू करेगा, जिनका मकसद स्थानीय सरकारों से लेकर तिब्बती स्कूलों और समुदायों तक तिब्बती पहचान को नष्ट करना है।

नए कानून के मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

अनिवार्य मंदारिन शिक्षा: इस कानून की मुख्य बात यह है कि स्कूलों में प्री-किंडरगार्टन से लेकर हाईस्कूल तक पढ़ाई की मुख्य भाषा के तौर पर मंदारिन-चीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह नीति सीधे तौर पर नई पीढ़ी पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे धीरे-धीरे तिब्बती भाषा की

व्यावहारिक अहमियत और रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है।

यह कानून 'विभिन्न मूल के लोगों के बीच परस्पर सामुदायिक माहौल' की बात करता है और ऐसी बस्तियों का प्रावधान करता है, जहां अलग-अलग मूल के समुदाय मिश्रित होकर रहें, ताकि पारंपरिक तिब्बती बस्तियों को भंग कर मिश्रित समुदाय बनाया जा सके। इससे परंपरागत तिब्बती समुदाय को छिन्न-भिन्न किया जा सकेगा, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तिब्बती संस्कृति को जीवित रखा है।

अधिनायकवादी निगरानी और नियंत्रण: 'सामाजिक शासन' के नाम पर यह कानून सभी तिब्बती मामलों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण स्थापित करता है और कथित 'बड़े खतरों' की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए 'वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता' के इस्तेमाल करने का समर्थन करता है।

देश से बाहर जाकर दमन: इस कानून की धारा- ६३ नस्लीय एकीकरण को कमजोर करने के आरोपी उन किसी भी व्यक्ति को पीआरसी (चीन) के अधिकार क्षेत्र में मानती है, जो एस्टोनिया सहित विभिन्न देशों में निवास करते हैं। इस धारा के तहत उन सब पर पर संभावित आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं।

इस कानूनी प्रावधान के कारण चीन की कम्युनिस्ट सरकार के पास चीनी राजनीतिक व्यवस्था के आलोचकों, तिब्बती और अन्य अल्पसंख्यक समर्थकों और निर्वासित तिब्बती समुदाय के सदस्यों की आवाज दबाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार मौजूद होने का खतरा है।

तिब्बत के लिए विनाशकारी परिणाम

निर्वासित तिब्बती सरकार के अनुसार, यह कानून पीआरसी के संविधान में ही प्रदत्त सार्थक क्षेत्रीय स्वायत्तता के मूल वादे पर घातक प्रहार करता है। यह कानून लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर करता है और तिब्बती भाषा को हाशिए पर धकेल देता है। साथ ही तिब्बतियों को व्यवस्थित रूप से उनकी पैतृक मातृभूमि, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं से अलग करता है। इसका मकसद सिर्फ एकीकरण नहीं, बल्कि विशिष्ट तिब्बती पहचान को धीरे-धीरे खत्म करके उसकी जगह चीनी सरकार द्वारा परिभाषित 'चीनी राष्ट्र (झोंगहुआ मिन्जु)' के प्रति निष्ठा को स्थापित करना है।

तिब्बती पहचान अपराध घोषित : इस कानून का मकसद 'चीनी राष्ट्र के लिए एक समुदाय बनने की मजबूत भावना पैदा करना' और एक ऐसा ढांचा बनाना है, जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा खुद को विशिष्ट तिब्बती पहचान से संबंधित बताने को राजनीतिक अपराध माना जा सके और तिब्बती धार्मिक रीति-रिवाजों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के पालन को 'अलगाववाद' की प्रवृत्ति मानकर उनका दमन किया जा सके।

इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले रीगिकोगु (एस्टोनिया की संसद) के सदस्य इस कानून की कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि तिब्बती लोगों की नजर में इसकी कोई नैतिक वैधता नहीं है। हालांकि यूरोपीय संसद और संयुक्त राष्ट्र पहले ही इस कानून के नतीजों पर गंभीर चिंता जता चुके हैं, लेकिन अब और भी मजबूत और निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।

रीगिकोगु (एस्टोनिया की संसद) के सदस्यों की मांग है कि:

पीआरसी (चीन) सरकार से इस कानून के खिलाफ औपचारिक रूप से कड़ा विरोध जताया जाए, इसे लागू न करने और इसे रद्द करने की मांग की जाए।

संयुक्त राष्ट्र के तहत आने वाली विभिन्न संस्थाओं और उसके तंत्रों से पीआरसी की आत्मसात करने की नीतियों की तत्काल समीक्षा करने और पीआरसी अधिकारियों द्वारा सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों के और उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साधनों का उपयोग करने को कहा जाए।

चीन-तिब्बत विवाद को ईमानदारी और परस्पर सम्मान के साथ बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक हल करने के लिए बीजिंग पर एकजुट होकर राजनयिक दबाव डाला जाए।

निर्वासन में तिब्बती संस्कृति और पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयासों में तिब्बती निर्वासित सरकार का समर्थन किया जाए।

◆ ९. तिब्बती पहचान पर हमला: सालों की दमनकारी निगरानी के बाद चीन ने फिर से लारुंग गार में बेरहम तोड़-फोड़ शुरू की

२१ जुलाई, २०२६

धर्मशाला। चीनी शासन ने लारुंग गार बौद्ध अकादमी में नए सिरे से विध्वंसकारी तोड़-फोड़ का दौर शुरू किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध संस्थान है, जो तिब्बत के पारंपरिक खाम प्रांत के कारजे जिले के सेर्थार (चीनी नाम: सेडा) में स्थित है, जिसे अब चीन के सिचुआन प्रांत में मिला दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, तोड़फोड़ लगभग १३ जुलाई २०२६ को शुरू हुई। शुरुआत में इसे जान-बूझकर रात में किया गया, ताकि सार्वजनिक रिकॉर्डिंग, मीडिया रिपोर्टिंग और सैटेलाइट निगरानी से बचा जा सके, लेकिन अब यह खुलेआम दिन के उजाले में भी होने लगा है। १५ जुलाई तक, कम से कम छह इमारतों को तोड़ा जा चुका है और आने वाले हफ्तों और महीनों में अधिकारी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लगभग १,०६० आवासों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं।

यह नई कार्रवाई दशकों से चल रहे सरकार-प्रायोजित सांस्कृतिक विनाश के अभियान का हिस्सा है। २००१ और २०१६-२०१७ में हुई भारी तोड़फोड़ में मठ की ७,००० से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया गया था और हजारों निवासियों को जबरन वहां से निकाल दिया गया था। इसके बाद भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ने तिब्बती बौद्ध संस्थान पर अपनी पकड़ को और कड़ा करना जारी रखा है। २०१९ में, वहां नए लोगों के दाखिले पर सख्त रोक और २४ घंटे की निगरानी लागू की गई। इसके बाद, २०२४ के आखिर में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती, हेलीकॉप्टर से निगरानी और रहने वालों की संख्या पर सीमा तय करने जैसे कड़े कदम उठाए गए। खबरों के अनुसार, पिछले साल चीनी अधिकारियों

ने लारुंग गार बौद्ध अकादमी से १,००० से ज्यादा तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों को निकाल दिया। इसकी वजह यह बताई गई कि उनके पास रहने के सही कागजात नहीं थे, जबकि असल में अधिकारियों ने बेरहमी से वहां रहने वाले धार्मिक लोगों की संख्या ६,००० से घटाकर ५,००० करने का आदेश दिया था।

हालांकि, चीन ने तिब्बती विरासत को गैर-कानूनी तरीके से नष्ट करने और तिब्बती पहचान की खुलेआम अनदेखी करने का दुष्टतापूर्ण कार्रवाई तिब्बत पर कब्जे के समय से ही चला रखी है, लेकिन इस बार की गई तबाही का समय गौर करने लायक है। यह घटना चीन द्वारा ०१ जुलाई, २०२६ को 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून' लागू करने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है। एकता को बढ़ावा देने के बजाय, यह कानून तिब्बतियों को जबरदस्ती मुख्य चीनी हान मूल के समुदाय में विलय करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बर्बर कानूनी हथियार के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है। चीनी संस्कृति में ढालने और 'प्रगति' का सब्जबाग दिखाकर चीनी सरकार तिब्बत की अनोखी भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और पहचान को मिटाने के लिए इस कानून का सुनियोजित तरीके से हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

इसमें कोई शक नहीं कि चीन की हरकतें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के साथ ही उसके अपने संविधान का भी गंभीर उल्लंघन हैं। चीन का संविधान चीन सरकार को तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए बाध्यकारी उपाय करता है। लेकिन, इसके बजाय चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बती मठ समुदायों को जबरन बेदखल करके और तिब्बती स्वशासन की जगह सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लागू करके तिब्बती जीवन के ताने-बाने को ही खत्म कर रहा है। २०१६ और २०१७ में लारुंग गार में की गई कार्रवाई के मानवीय नतीजे बहुत बुरे रहे हैं। इससे लोगों को गहरा मानसिक आघात पहुंचा और वहां के अवसादग्रस्त लोगों ने आत्महत्याएं कीं। उदाहरण के तौर पर, २०१६ में तोड़फोड़ के दौरान तिब्बती नन शेरिंग डोल्मा और सेमघा की मौत हो गई।

पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संसद, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, अमेरिकी सरकार और प्रमुख मानवाधिकार संगठनों जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय निकायों ने बार-बार आधिकारिक प्रस्ताव, संयुक्त बयान और औपचारिक घोषणाएं जारी करके लारुंग गार में बीजिंग द्वारा की जा रही सुनियोजित तोड़फोड़ और सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कार्रवाई की निंदा की है। चीन को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि ये शुरुआती निंदाएं कई साल पहले की गई थीं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय लारुंग गार में उसके जारी अपराधों को भूल गया है या यह तबाही जारी रहने पर चुप रहेगा। पीआरसी सरकार को लारुंग गार में सभी तरह की तोड़फोड़ रोकनी चाहिए, उस इलाके से अपनी सेना और प्रशासनिक बलों को हटाना चाहिए और तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के अपने अनिवार्य दायित्वों का पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

- डीआईआईआर के तब्बित एडवोकेसी सेक्शन के तहत संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधकिार डेस्क द्वारा तैयार रपिोर्ट

◆ १०. बेल्जियम, नीदरलैंड और स्पेन में सैकड़ों लोगों ने चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को रद्द करने की मांग की

०३ जुलाई, २०२६

ब्रसेल्स, ०१ जुलाई। बेल्जियम, नीदरलैंड और स्पेन में हजारों तिब्बतियों और उनके समर्थकों ने गत ०१ जुलाई को चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' का कड़ा विरोध किया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भले ही इस कानून का नाम सुनने में अच्छा लगे, लेकिन असल में यह तिब्बत और चीन अधिकृत अन्य क्षेत्रों में दशकों से चल रही जबरन आत्मसातीकरण की नीतियों को कानूनी वैधता प्रदान करता है।

ये विरोध प्रदर्शन उस वैश्विक अभियान का हिस्सा थे, जिसमें इस कानून द्वारा तिब्बती पहचान, भाषा, धर्म और संस्कृति को खत्म करने के खिलाफ दुनिया भर के तिब्बतियों और समर्थकों ने गहरी चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कानून चीनी सरकार के उस कानूनी अधिकार को और मजबूत करता है जिसके तहत तिब्बतियों और अन्य लोगों पर आत्मसातीकरण की नीतियों को और कठोर तरीके से लागू किया जा सकता है।

ब्रसेल्स में यह प्रदर्शन- इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी), लुंगटा तिब्बत सपोर्ट ग्रुप, वर्ल्ड उग्यूर कांग्रेस और स्थानीय तिब्बती संघों द्वारा 'तिब्बत कार्यालय' के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें २०० से अधिक तिब्बती और उनके समर्थक यूरोपीय संसद के बाहर 'प्लेस डू लक्जमबर्ग' पर जमा हुए। उन्होंने यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे इस नए कानून को लागू होने से रोकें और इस कानून को बनाने में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएं।

यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस प्रदर्शन में भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। इनमें तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह- आईपीजीटी के अध्यक्ष डेनियस जालिमास, चीन के साथ संबंधों के लिए संसद के प्रतिनिधिमंडल- डी-सीएन की उपाध्यक्ष मार्केटा ग्रेगोरोवा, धर्म, विश्वास और अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर अंतर-समूह की अध्यक्ष मिरियम लेक्समैन और डानुसे नेरुडोवा शामिल थे।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद डी. जालिमास ने याद दिलाया कि यूरोपीय संसद ने पहले भी परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकार में चीन के हस्तक्षेप के प्रयासों को खारिज कर दिया था। इसी तरह, यह संसद नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को भी खारिज करती है और इस बात पर जोर देती है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।

सांसद एम. ग्रेगोरोवा ने कहा कि वह तिब्बतियों के साथ एकजुटता दिखाने

और उनकी चिंताओं को सुनने के लिए इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उन्होंने इस कानून को सांस्कृतिक विनाश को बढ़ावा देने वाला बताया और तिब्बती लोगों का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया।

सांसद अप्रैल में यूरोपीय संसद में इस कानून को लेकर चिंता जताने वाले सांसद डी. नेरुडोवा ने कहा कि कानून का शीर्षक गुमराह करने वाला है और इसका असली एकता से कोई खास लेना-देना नहीं है। उन्होंने सीमा-पार जाकर दमन करने के अधिकार ग्रहण करने के खिलाफ भी चेतावनी दी और जोर दिया कि यूरोप को आर्थिक हितों के लिए मानवाधिकारों की बलि नहीं देनी चाहिए।

सांसद एम. लेक्समैन ने प्रदर्शनकारियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यूरोप को उन मूल्यों की याद दिलाई, जिन पर यूरोपीय संघ की नींव रखी गई थी, जैसे आजादी, लोकतंत्र और कानून का शासन। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों के लिए इन आजादियों की रक्षा की जानी चाहिए।

आईपीजीटी के सह-अध्यक्ष सांसद एच. हाइड ने अपने भाषण में कहा कि यूरोपीय संसद ने चीन को मजबूत, साफ और सीधा संदेश भेजा है कि वह इस कानून को वापस ले।

'तिब्बत कार्यालय' की प्रतिनिधि गेनखांग और आसीटी के नीति-निदेशक विंसेंट मेटेन ने इस कानून के व्यापक असर, खासकर इसके अनुच्छेद-६३ को लेकर चिंता जताई। उनका तर्क था कि इससे चीन की सीमाओं के बाहर भी दमन को बढ़ावा मिल सकता है। प्रतिनिधि गेनखांग ने यूरोपीय संघ और अन्य सरकारों से अपील की कि वे इस कानून का विरोध करने में यूरोपीय संसद की मिसाल का पालन करें। साथ ही, उन्होंने तिब्बतियों, खासकर निर्वासित तिब्बतियों से अपनी भाषा, पहचान और संस्कृति को बचाए रखने का आग्रह किया।

प्रदर्शन में एक प्रतीकात्मक पहलू जोड़ते हुए, तिब्बती वीकेंड स्कूल के बच्चों ने तिब्बती भाषा पर मंडरा रहे खतरों के विरोध में तिब्बती भाषा में संदेश लिखे पोस्टर लेकर हिस्सा लिया।

नीदरलैंड में, तिब्बती कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक समूह एम्स्टर्डम के मशहूर डैम स्क्वायर पर इकट्ठा हुआ और चीन के 'नस्लीय एकीकरण कानून' को तुरंत रद्द करने की मांग की। यह प्रदर्शन 'तिब्बत सपोर्ट ग्रुप नीदरलैंड' ने आयोजित किया था। इसमें इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, नीदरलैंड में तिब्बती समुदाय, स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत, उग्यूर, हांगकांग और कैंटोनीज संगठनों के साथ-साथ 'एंटी-सीसीपी नीदरलैंड' भी शामिल हुए। कानून को वापस लेने की मांग के अलावा, प्रतिभागियों ने आने-जाने वाले लोगों से बातचीत की और उन्हें तिब्बतियों और अन्य लोगों पर इसके संभावित असर के बारे में जागरूक किया।

स्पेन में तिब्बती समुदाय ने सुबह-सुबह कासा डेल तिब्बत और तिब्बत समर्थकों के साथ मिलकर चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने नए कानून के संबंध में अपनी चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकारी भवनों के पास एक जन जागरूकता अभियान और विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया।

बेल्जियम, नीदरलैंड और स्पेन में प्रदर्शन चीन के नस्लीय एकीकरण कानून के कार्यान्वयन के जवाब में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय अभियान का हिस्सा थे। प्रदर्शनकारियों ने तीनों देशों में एकीकृत संदेश दिया, जिसमें चीनी सरकार से कानून को रद्द करने का आग्रह किया गया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बती पहचान, भाषा, संस्कृति और मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा का समर्थन जारी रखने का आह्वान किया गया।

- तिब्बत कार्यालय, ब्रुसेल्स की रिपोर्ट

◆ ११. विरोध की आग: लोबगा रंगजेन की आत्मदाह पर यूरोप में बसे तिब्बती समुदाय ने जेनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय की अगुआई में शोक मनाया।

१४ जुलाई, २०२६

जेनेवा। चीन द्वारा अपने नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' को लागू करने के एक दिन बाद ही लोबगा रंगजेन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह कर लिया। रंगजेन इस कानून को तिब्बती पहचान, संस्कृति, भाषा और धर्म के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा मानते थे। विरोध के इस चरम उपाय के जरिए, उन्होंने चीनी सरकार से उन नीतियों पर पुनर्विचार करने और उन्हें रद्द करने की अपील की, जिनसे उनके अनुसार तिब्बती लोगों की विशिष्ट पहचान और अधिकारों को और नुकसान पहुंचने वाला है। साथ ही, उन्होंने तिब्बत में मानवाधिकारों से जुड़े मौजूदा मुद्दों की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

चीनी अत्याचारों के खिलाफ आत्मदाह करने वाले वे न तो पहले तिब्बती थे और न ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने ऐसा कदम उठाने वाले पहले व्यक्ति। हालांकि, इतिहास में वे ऐसे पहले तिब्बती जरूर बन गये, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण मुख्यालय पर ऐसा कदम उठाया। उनके द्वारा चुनी गई जगह का गहरा प्रतीकात्मक महत्व था। किसी व्यक्ति विशेष या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, उन्होंने ऐसी जगह चुनी जो अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवीय गरिमा की उम्मीद का प्रतीक है। उनके इस कदम से शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति और अहिंसात्मक रूप से बातचीत के सिद्धांतों में उनके विश्वास का पता चलता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अपने शरीर में आग लगाने के बाद रंगजेन संयुक्त राष्ट्र की इमारत के सामने एक जलते हुए सीधे दीपक की तरह खड़े रहे और अंतिम क्षण में उन्होंने इमारत की ओर झुककर उसे नमन किया। कई तिब्बतियों के लिए, यह भाव प्रार्थना, उम्मीद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में विश्वास का प्रतीक था। यह उनके इस विश्वास का प्रतीक था कि उनकी अंतिम अपील सुनी जाएगी और इससे तिब्बती मुद्दे के शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में नए प्रयासों को प्रेरणा मिलेगी।

०३ जुलाई को जर्मनी में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने बर्लिन और देश के अन्य स्थानों पर एक आपातकालीन प्रार्थना सभा और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्थानीय मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल करके तिब्बत के हालात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

उसी दिन, ऑस्ट्रिया में तिब्बती समुदाय ने वी-टीएजी ऑस्ट्रिया और 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' जैसे युवा संगठनों के साथ मिलकर वियना, साल्जबर्ग, स्टायरमार्क/ग्राज और लिंज में प्रार्थना सभाएं और एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के जरिए एकता, मजबूती और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के साझा संदेश दिए गए।

सबसे बड़ा यादगार कार्यक्रम स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्थित 'तिब्बत कार्यालय' के समन्वय से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से यूरोप में तिब्बती निर्वासित समुदाय के बीच देश की अहम भूमिका और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति व मानवाधिकार कार्यों के केंद्र के रूप में इसके लंबे समय से चले आ रहे महत्व को रेखांकित किया गया।

अगले दिन यानी, ०४ जुलाई को जिनेवा के तिब्बती समुदाय ने एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की। इसमें स्थानीय तिब्बती समुदाय के सदस्य वहां रंगजेन की याद में इकट्ठा हुए और संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संस्थाओं के केंद्र- जिनेवा की खास स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए।

अगले दिन ०५ जुलाई को स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के तिब्बती समुदाय द्वारा आयोजित 'मोनलम' स्मारक प्रार्थना समारोह के लिए सैकड़ों तिब्बती''तिब्बत इंस्टीट्यूट रिकॉन' में एकत्र हुए।

प्रार्थना समारोह के दौरान, प्रतिनिधि थिनले चुक्की, एडवोकेसी ऑफिसर फुंट्सोक टोपग्याल, अकाउंटेंट तेनजिन चोसांग और यूरोपीय यूनियन-चीन संपर्क अधिकारी सांग्ये क्याब के साथ-साथ तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रार्थना की और 'रंगजेन' के जीवन, बलिदान और तिब्बती एकता के लिए उनकी अटूट निश्चय को श्रद्धांजलि दी।

- तिब्बत कार्यालय, जिनेवा की रिपोर्ट

◆ १२. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी का विरल तिब्बत दौरा, चीन के नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को लागू करने और जबरन विलयीकरण की नीतियों को और मजबूत करने का संकेत

२४ जुलाई, २०२६

- इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, २३ जुलाई २०२६

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक, वांग हुनिंग ने तिब्बत का दौरा किया, जो चीनी अधिकारियों द्वारा विरले ही किया जाता है। यह दौरा बीजिंग के नए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' के ०१ जुलाई को लागू होने के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ। यह दौरा इस बात का संकेत है कि चीन इस कानून को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कानून तिब्बत में लोगों को मुख्यधारा में जबरन आत्मसात करने, वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला है।

पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) के अध्यक्ष वांग हुनिंग १९ से २२ जुलाई तक तिब्बत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजधानी ल्हासा और उसके आसपास के न्गारी व अन्य इलाकों का निरीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान वांग ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत में शासन की मुख्य प्राथमिकताओं में नए 'नस्लीय एकीकरण कानून' को लागू करना, तिब्बती बौद्ध धर्म को 'चीनी रंग में ढालने' की कोशिशों को तेज करना और 'सामाजिक स्थिरता बनाए रखना' शामिल होना चाहिए। 'सामाजिक स्थिरता बनाए रखना' वह शब्द है, जिसका इस्तेमाल बीजिंग असहमति को दबाने के लिए बनाई गई नीतियों और सुरक्षा उपायों के लिए करता है।

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, वांग ने अपने दौरे के दौरान बार-बार इस बात पर जोर दिया, 'हमें नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। इस कानून के अनुसार नस्लीय मामलों के प्रबंधन की क्षमता और स्तर में सुधार करना होगा और सभी विकास कार्यों में नस्लीय एकीकरण और प्रगति के महत्व को बढ़ावा देना होगा। देश में धर्म को 'चीनी रंग में ढालने' की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने और धार्मिक मामलों में कानून के शासन को मजबूत करने की जरूरतों के अनुसार, हमें तिब्बती बौद्ध धर्म को समाजवादी समाज के अनुकूल ढलने के लिए लगातार मार्गदर्शन देना होगा।'

वांग का यह दौरा तिब्बती कार्यकर्ता लोबगा रंगजेन द्वारा ०२ जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह करने के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है। यह घटना चीन द्वारा नए नस्लीय एकीकरण कानून को लागू करने के एक दिन बाद हुई थी। पार्टी के मुख्य विचारक और शी जिनपिंग के राजनीतिक सलाहकारों में से एक होने के नाते, वांग के निरीक्षणों पर बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि वे पार्टी नेतृत्व की सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

वांग के इस दौरे पर टिप्पणी करते हुए इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत की अध्यक्ष टेंको ग्यात्सो ने कहा, 'वांग हुनिंग का दौरा यह दिखाता है कि बीजिंग तिब्बत में अपनी जबरन आत्मसातीकरण को तेजी से लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कानूनी और राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाह रहा है। 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून' के लागू होने के कुछ ही हफ्तों बाद हुए इस उच्चस्तरीय दौरे और वांग द्वारा बार-बार नस्लीय एकीकरण पर जोर देने से पता चलता है कि चीनी सरकार नस्लीय एकीकरण के नाम पर तिब्बती पहचान को मिटाने वाली नीतियों को संस्थागत बनाने को कितनी अहमियत देती है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय और दुनिया की सरकारों को इस कानून को एक खतरनाक कानूनी ढांचा के तौर पर देखना चाहिए, जिसे तिब्बत की अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और पहचान को कमजोर करने और आखिरकार मिटाने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें चीन से इसे रद्द करने की मांग करनी चाहिए।'

आईसीटी के सूत्रों ने बताया कि वांग के दौरे के दौरान अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा पाबंदियां लगाई थीं। वांग ने ल्हासा में सेरा मठ और न्गारी प्रिफेक्चर के सबसे पुराने मठों में से एक- थोलिंग मठ का निरीक्षण भी किया।

वांग ने 'शियाओकांग' या सीमावर्ती गांव और पुरंग, समधा (जंडा) और गार के आस-पास के इलाकों के अन्य गांवों का भी निरीक्षण किया। सूत्रों ने आईसीटी को बताया कि वांग के दौरे को देखते हुए मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया था, लोगों की आवाजाही पर कड़ी रोक थी और ल्हासा व न्गारी में सुरक्षा चौकियों को और मजबूत किया गया था। उन्होंने बताया कि न्गारी में स्थानीय अधिकारियों ने दौरे के दौरान तीर्थयात्रियों के पवित्र कैलाश पर्वत जाने पर भी रोक लगा दी थी।

इस दौरान, वांग ने सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित और विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। इन सीमावर्ती इलाकों में चीन ने अपने विस्तारवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'दोहरे उद्देश्य' (नागरिक-सैन्य) वाले गांवों को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया है। ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने और तिब्बत को प्राचीन काल से चीन का अभिन्न अंग दिखाने की सीसीपी की चल रही कोशिशों के अनुरूप, स्थानीय अधिकारियों से कहा कि वे '... तिब्बती ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक कलाकृतियों और सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा और उपयोग को मजबूत करें, जो नस्लीय समूहों के बीच आदान-प्रदान, बातचीत और एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को दिखाते हों और चीनी सभ्यता की विशालता और भव्यता को प्रदर्शित करते हों।'

वांग के साथ यूनाइटेड वर्क फ्रंट डिपार्टमेंट के प्रमुख ली गंजिए भी थे। गंजिए ने 'चीनी राष्ट्र के लिए समुदाय की मजबूत भावना पैदा करने, नस्लीय एकीकरण और प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल क्षेत्र' के निर्माण को बढ़ावा देने और ऐसे मॉडल क्षेत्रों के निर्माण को और गहरा करने के उद्देश्य से प्रचार को तेज करने का भी आह्वान किया। उनके निर्देश नए नस्लीय एकीकरण कानून, खासकर इसके एक और अनुच्छेद- ५६ की जरूरत को दिखाते हैं। इस अनुच्छेद में कानून के बारे में प्रचार करने और हर साल सितंबर के चौथे हफ्ते को इस नए कानून के लिए 'राष्ट्रीय प्रचार सप्ताह' के तौर पर मनाने का प्रावधान किया गया है।

पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्यों का तिब्बत दौरा आम तौर पर तब होता है, जब बीजिंग उस इलाके में किसी बड़े राजनीतिक कदम या रणनीतिक प्राथमिकता को मजबूत कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर, २०२३ और २०२४ में वांग के तिब्बत दौरों के दौरान, उन्होंने तिब्बत के प्रशासन के लिए शी जिनपिंग की 'नए युग' वाली रणनीति को बढ़ावा दिया और नस्लीय एकीकरण, सीमा सुरक्षा और तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी रंग में ढालने पर जोर दिया।

◆ १३. तिब्बती राजनीतिक कैदियों की विवरणिका- सुल्ट्रिम ग्यात्सो

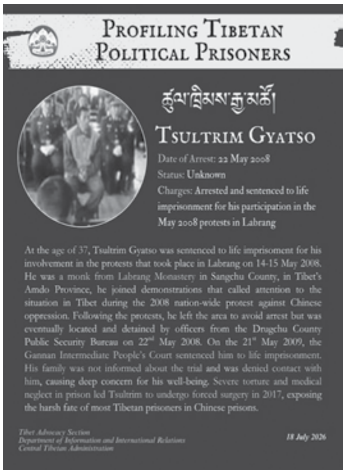

नाम: सुल्ट्रिम ग्यात्सो

गिरफ्तारी: २२ मई, २००८

वर्तमान स्थिति: अज्ञात

आरोप: लाब्रंग में २००८ में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार हुए और उम्रकैद की सजा दी गयी।

३७ साल की उम्र में, सुल्ट्रिम ग्यात्सो को १४-१५ मई २००८ को लाब्रंग में हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह तिब्बत के आमदो प्रांत के सांगचू काउंटी स्थित लाब्रंग मठ में भिक्षु थे। उन्होंने २००८ में चीनी दमन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान तिब्बत के हालात की ओर ध्यान दिलाने के लिए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। विरोध-प्रदर्शनों के बाद, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह उस इलाके से चले गए, लेकिन आखिरकार २२ मई, २००८ को ड्रगचू काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। २१ मई, २००९ को गन्नन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके परिवार को मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और उन्हें उनसे संपर्क करने की भी इजाजत नहीं मिली, जिससे उनकी सलामती को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई। जेल में बुरी तरह प्रताड़ित किए जाने और इलाज में लापरवाही के बाद सुल्ट्रिम को २०१७ में जबरदस्ती सर्जरी करवाई गयी। उनके बारे में इस विवरण से पता चलता है कि चीनी जेलों में ज्यादातर तिब्बती कैदियों के साथ किस तरह का कठोर बर्ताव किया जाता है।

१८ जुलाई, २०२६
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन
सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग
तिब्बत एडवोकेसी प्रभाग

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः coordinator@indiatibet.net

July, 2026, Years: 47 Issue: 7 Regd No. : RNI 34636-79

- न्यूयॉर्क शहर में UN हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बती एक्टिविस्ट लोबगा रंगज़ेन ने खुद को आग लगा ली, जिससे उनकी मौत हो गई।

ITCO और हिमालय परिवार ने नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा का 91वां जन्मदिन मनाया